



दुर्लभ मार्श फ्रिटिलरी प्रजाति की तितली फिर से ब्रिटेन की लेक डिस्ट्रिक्ट वैली में पनप रही है क्योंकि यहां चरने वाली भेड़ों को हटा दिया गया है। इनकी जगह अब यहां पर खच्चर और अन्य मवेशी लाए गए हैं। कम्ब्रिया से 19 साल पहले यह तितली लुप्त हो गई थी पर एक सरकारी पुनर्वास कार्यक्रम के बाद ये पुनः यहां पनप रही है। इस बार गर्मी के मौसम में ये तितलियाँ स्विट्ज़लैंड वैली तक गईं, जो कि रॉयल सोसायटी ऑफ़ द प्रोटेक्शन ऑफ़ बर्ड्स (आर.एस.पी.बी.), हॉर्सवॉटर, का एक भाग है। यहां संरक्षणविद् इस प्रजाति का पुनर्वास करने पर विचार कर रहे थे। तथापि, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि, इस स्थान पर चराई में कुछ मूल परिवर्तन किए गए। ये तितलियाँ इसलिए स्विट्ज़लैंड वैली लौटीं, क्योंकि, यहां इनके फूड प्लांट, "डैविल्स बिट स्केबिअस" की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई। पूर्व में घाटी के चारागाहों में मोटी घास की भरमार थी, जिसे भेड़े नहीं खाती थीं, फिर, आर.एस.पी.बी. हर साल यहां पर स्थानीय खच्चरों को लेकर आए, जिन्होंने धीरे-धीरे करके मोटी घास को साफ कर दिया। हॉर्सवॉटर के साइट मैनेजर ली स्कोफील्ड ने कहा, "अगले ही बसंत में यहां हीथ स्पॉट ऑर्किड्स के फूल खूब खिलें, फिर बाद में भारी मात्रा में डैविल्स बिट स्केबिअस पनपे।" विशेषज्ञों ने कहा कि, गत कुछ वर्षों से इन फूलों की संख्या बढ़ी है और इसका श्रेय जाता है खच्चर के पुनर्वास को। विशेषज्ञों का कहना है कि, अगर हमने यह बदलाव नहीं किया होता तो ये पौधे नहीं पनपते और तितलियाँ भी नहीं आतीं। दो स्कॉटिश प्रजातियों, हाइलैण्ड एवं गैलोवे मवेशियों की भी वापसी की गई। नैचुरल हायड्रॉलजी बहाल की गई जिससे फूलों के पनपने के लिए नमी वाले क्षेत्र तैयार हुए। कम्ब्रिया में मार्श फ्रिटिलरी का प्राकृतिक विस्तार बटरफ्लाई कंजर्वेशन संस्था द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम की जीत है।

कर्नाटक सरकार अपनी चुनावी "गारंटियों" के क्रियान्वयन को "शो केस" करेगी

-लक्ष्मण वेंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जुलाई। कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में बुधवार को पूरा दिन मीडिया को कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना के बारे में बताया, जिसमें हरेक घर की महिला मुखिया को 2000 ₹. प्रतिमाह दिया जाएगा। पार्टी ने बताया कि कर्नाटक सरकार चुनावी वायदों को निभाने के लिए कृत संकल्प है, इस प्रकार पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व देशभर में सुशासन देने और चुनावी वायदों को पूरा करने का अपना इरादा जताया।

कर्नाटक सरकार के प्रोग्राम की

क्या आपको कम सुनाई देता है?
ऑटोमेटिक कान की मशीनों स्पीच थेरेपी कॉकिलियर इम्प्लांट, ऑटिजम डिजिटल स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क - 94602 07080

भाजपा के 10 विधायक निलंबित

बैंगलूर, 19 जुलाई। कर्नाटक में भाजपा के 10 विधायकों को बुधवार को विधानसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन में अशोभनीय और अपमानजनक आचरण को लेकर यह कार्रवाई हुई। विधानसभा सत्र से भाजपा के विधायकों को सत्र के लिए निलंबित

- इस निलंबन के विरोध में भाजपा और जे.डी.एस. ने कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट होकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया।

किए जाने के बाद भाजपा और जे.डी.एस. ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। इस बीच, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के ये नेता पार्टी विधायकों के (शेष पृष्ठ 5 पर)

गृहलक्ष्मी योजना के तहत लगभग एक करोड़ गृहणियों को दो हजार रुपये दिये जायेंगे उनके बैंक अकाउंट में

घोषणा दिल्ली में करते हुए ए.आई.सी.सी. प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस योजना के द्वारा कांग्रेस, कर्नाटक की राज्य सरकार और वहां की महिलाओं ने जानबूझकर महंगाई बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है।

यह विश्व की सबसे बड़ी "डायरेक्ट बेनिफिट" योजना है जिसमें एक करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 2000 ₹. हस्तांतरित किए जाएंगे ताकि बढ़ती महंगाई से जूझने में उन्हें थोड़ी मदद मिल सके।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में जो पांच गारंटियां दी थीं उनमें से यह चौथी है, जिसे क्रियान्वित कर दिया गया है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा तो पहले ही दे दी गई है।

राज्य सरकार ने अन्नभाग योजना भी शुरू कर दी है जिसमें बी.पी.एल. परिवार के हरेक सदस्य को प्रतिमाह दस किलो चावल मिलना था। पर चूंकि केन्द्र सरकार ने एफ.सी.आई. को कर्नाटक

- इसी प्रकार सभी महिलाओं को सरकारी बसों में "फ्री" यात्रा की सुविधा दी गयी है।
- साथ ही कर्नाटक सरकार अन्न भाग्यम् स्कीम के तहत हर बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को 15 किलोग्राम चावल नहीं दे पा रही, एफ.सी.आई. द्वारा चावल उपलब्ध नहीं कराने के कारण, अतः वह हर बी.पी.एल. परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह चावल के एवज में 140 ₹. उसके खाते में जमा करायेंगी।
- छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकार भी कर्नाटक की भांति लोकसभा चुनाव से पूर्व, इस क्रियान्वयन को "शो केस" करना चाहती हैं। पर, क्या विधानसभा चुनाव से पूर्व 5 महीनों में यह क्रियान्वयन संभव है?

को चावल देने से रोक दिया इसलिए सरकार ने हरेक व्यक्ति को बैंक खाते में प्रतिमाह 170 ₹. देना शुरू कर दिया ताकि 5 किलोग्राम चावल की कमी पूरी की जा सके। और जब तक सरकार चावल प्राप्त नहीं कर लेती तब तक यह योजना जारी रहेगी।

सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री द्वारा इन

योजनाओं को रेवड़ी बताने को खारिज कर दिया और कहा कि गरीबों के हाथ में पैसा देना सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स है। और इसे धरातल पर और ज्यादा आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। जैसे 2009 की आर्थिक मंदी में महानेरगा ने किया था।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

रेलवे जनरल बोगियों में 20 रु. में पूड़ी-सब्जी उपलब्ध करायेगा

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (वार्ता)। देश में चुनावी मौसम शुरू होते ही भारतीय रेलवे को गरीबों की याद आने लगी है और इसी क्रम में अब जनरल डिब्बे में यात्रा करने वालों के लिए मात्र 20 रुपये में पूड़ी-सब्जी उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने गरीब यात्रियों के लिए 20 रुपये में सात

- आई.आर.सी.टी. सी. केन्द्र सरकार की इस योजना का संचालन करेगा। इसके अलावा 50 रुपये में चावल और स्नैक्स मील का मैन्चू भी शुरू किया गया है।

पुड़ियां (175 ग्राम), आलू की सब्जी (150 ग्राम) और अचार (12 ग्राम) की इकॉनोमी मील शुरू की है।

इसके अलावा 50 रुपये में स्नैक्स मील का मैन्चू भी शुरू किया गया है इस करीब 350 ग्राम के इस मील में चावल और छोले/राजमा, खिचड़ी, छोले एवं (शेष पृष्ठ 5 पर)

विपक्ष व भाजपा के बीच "माइन्ड गेम्स" शुरू हुए

जनता के मन में एक दूसरे के लिये अविश्वास पैदा करने के इस खेल में संभवतया भाजपा कुछ आगे है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जुलाई। भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. का मुकाबला करने के लिये विपक्षी मोर्चा "इंडिया" की बाकायदा घोषणा होते ही दोनों तरफ से आम जनता की कल्पना एवं सोच पर कब्जा करने दिमागी एवं मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो गये हैं। दोनों ही गठबंधनों ने लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति अविश्वास के बीज बोना शुरू कर दिया है।

जहाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला गठबंधन कह रहा है कि विपक्षी मोर्चा "इंडिया" भ्रष्ट लोगों का जमघट है तथा एन.डी.ए. में "एन" अक्षर न्यू इंडिया (नया भारत), "डी" डवल्लड (विकसित) तथा "ए" एम्प्लेसमेंट ऑफ द पीपुल (जनाकांक्षा) के लिये है, वहीं विपक्ष ने आज हिन्दी में एक नई टैग लाइन "जीतेगा भारत" शुरू की ताकि आर.एस.एस. तथा भाजपा के उस व्यापक दुश्चचार तंत्र का जवाब दिया जा सके जिनसे विपक्षी फ्रंट का नाम (शेष पृष्ठ 5 पर)

- बैंगलूर बैठक के बाद पहले तो यह फैलाया गया, बिहार के भाजपा नेता सुशील मोदी की ओर से कि, नीतीश कुमार को संयोजक घोषित नहीं किया गया, अतः वे विपक्ष की प्रैस कॉन्फ्रेंस में अनुपस्थित रहे।

- फिर, भाजपा की ओर से यह उछाला गया कि, विपक्ष के नये संगठन का नाम इण्डिया रखा गया है, न कि, भारत।

- फिर यह विवाद उठाया गया कि, इण्डिया नाम, किस के उपजाऊ दिमाग की उपज थी, राहुल की या ममता बनर्जी की।

- विपक्ष ने एक-एक करके इन अफवाहों का जवाब दिया। नीतीश कुमार प्रैस कॉन्फ्रेंस में अनुपस्थित थे, क्योंकि, उनकी फ्लाइंग जल्दी थी।

- नीतीश उखड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इण्डिया नाम देने के मंथन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पहले तो, "सेव इण्डिया अलायन्स" और "वी फॉर इण्डिया" नाम सुझाए थे, पर, जब इण्डिया नाम पर मोटा-मोटी सहमति बनती दिखी तो, उन्होंने इण्डिया नाम स्वीकार किया।

- हालांकि, इण्डिया नाम का सुझाव राहुल गांधी ने दिया था, पर, उन्होंने यह सुझाव देते हुए कहा था कि, नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी को देना चाहिये। इसीलिये, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखते हुए राहुल को "माय फैवरेट" (मेरा प्रिय) कह कर संबोधित किया था।

- इण्डिया अंग्रेजी नुमा लगने की शिकायत के प्रत्युत्तर में उद्धव ठाकरे के सुझाव पर नयी "टैग लाइन" जोड़ी गयी, "जीतेगा भारत"।

लोकसभा चुनाव क्या केवल "इण्डिया" व एन.डी.ए. के बीच ही है?

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जुलाई। अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों में एन.डी.ए. बनाम इंडिया की लड़ाई में, इनमें शामिल दलों की जो सूची सामने आई है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु ध्यान में नहीं आया है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु है- उन तटस्थ दलों की संभावित भूमिका, जो बैंगलूर तथा दिल्ली में हुई दो मीटिंगों में से किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुये हैं, दोनों ही गठबंधनों से दूर रहे हैं। इनमें से मजबूत क्षेत्रीय दल जैसे बीजू जनता दल, वाय.एस.आर.सी.पी., भारत राष्ट्र समिति और शिरोमणि अकाली दल है जबकि इसी श्रेणी के अन्य दलों जैसे- बसपा, जद (एस.), ए.आई.एम.आई.एम. तथा तेलुगु देशम पार्टी की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इन पार्टियों के नेता ज्यादातर भाजपा के प्रति नर्म रख रखते दिखाई देते हैं। लेकिन जब चुनावी दौड़-पेचों की बात आती है, तो यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन पार्टियों के नेता कौन सा करवट लेंगे। जहाँ एन. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सहित, कुछ पार्टियाँ भाजपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के लिये बातचीत करती बताई जा रही हैं, वहीं तेलंगाणा के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर

- "न्युट्रल" पार्टियाँ भी काफी महत्व रखती हैं, हालांकि पार्टियों की संख्या की दृष्टि से भाजपा इस क्षेत्र में भी आगे है, क्योंकि, विपक्ष की बैठक में 26 राजनीतिक पार्टियों की तुलना में, एन.डी.ए. के सम्मेलन में 39 पार्टियाँ थीं।

- पर, एन.डी.ए. के सम्मेलन में 11 पार्टियाँ तो नॉर्थ ईस्ट की थीं तथा बाकी छोटे-छोटे दल थे जिनका प्रभाव काफी सीमित क्षेत्र में ही है।

- दूसरी ओर विपक्ष की बैठक में पांच मु.मंत्री थे, ममता बनर्जी, स्टालिन, केजरीवाल, हेमन्त सोरेन, व नीतीश कुमार।

- और भी कई स्थापित नेता, जैसे, शरद पवार, सोनिया गांधी, लालू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव व उद्धव ठाकरे उपस्थित थे।

राव भी भाजपा की ओर झुकते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ इस बिन्दु को लेकर भाजपा राहत में नजर आ रही है, लेकिन वह इन पार्टियों के समर्थन को सुनिश्चित मानकार नहीं चलना चाहेगी। बीजू जनता दल ने नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के विपक्ष के आह्वान को अस्वीकार कर दिया तथा नोटबंदी, सर्विकल स्ट्राइक तथा अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे

मुद्दों पर एन.डी.ए. का समर्थन किया था, उसी बीजू जनता दल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह संसद के मानसून सत्र में भाजपा का सामना करेगी।

भाजपा ने विपक्षी एकता के प्रयासों को खारिज करने की कोशिश करते हुये, दिल्ली में एन.डी.ए. की एक विपक्ष से भी बड़ी मीटिंग कर डाली, जिसमें 39 दलों के नेता शामिल हुये, जबकि बैंगलूर (शेष पृष्ठ 5 पर)

'अमेरिका व चीन के बीच संबंध इतने खराब हैं कि, छोटी सी गलतफहमी भी विकराल रूप धारण कर सकती है'

हैनरी किसिंजर, जो 1969 से 1976 तक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और जिन्हें श्रेय जाता है, 1970 के दशक में चीन व अमेरिका के बीच पहली बार "डायलॉग" स्थापित करने का, आज चीन-अमेरिका संबंधों की स्थिति से काफी दुखी हैं

- किसिंजर के अनुसार, आज चीन व अमेरिका के संबंधों की वही स्थिति है, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैण्ड व जर्मनी के संबंधों की थी।
- दोनों देशों में काफी आपसी व्यापार व व्यवसायिक लेन-देन था, पर, इंग्लैण्ड को आशंका थी कि, जर्मनी यूरोप पर छाना चाहता है तथा जर्मनी की यह धारणा थी कि, इंग्लैण्ड उसे अन्तर्राष्ट्रीय पावर नहीं बनने देना चाहता।
- डायलॉग के अभाव में यह अविश्वास इतना बढ़ा कि, प्रथम विश्व युद्ध में इसका "क्लाइमैक्स" हुआ।
- चीन व अमेरिका, दोनों अपने आप को विशेष "सभ्यता" मानते हैं, जिसका अनुसरण पूरे विश्व को करना चाहिये। अगर चीन व अमेरिका में भी "डायलॉग" नहीं जारी रहा तो, यह प्रतिस्पर्धा युद्ध में परिवर्तित हो सकती है।

किसिंजर 1969-76 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेंक्रेटरी ऑफ स्टेट (विदेश मंत्री)

थे तब अमेरिका की विदेश नीति को आकार देने में उनकी अहम भूमिका थी। अमेरिका के जाने-माने शिक्षाविद्

प्रो. थॉमस ए. श्वार्ट्ज, जिन्होंने हैनरी किसिंजर एण्ड अमेरिकन पावर: ए पोलिटिकल बायोग्राफी" किताब लिखी

है, के अनुसार भारत व चीन के रिश्ते बनाने में रणनीतिकार के रूप में किसिंजर की अहम भूमिका थी, उन्होंने

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की रैगुलर जमानत मंजूर की

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 2002 दंगों से संबंधित कथित मनगढ़ंत सबूत बनाने और गवाहों को प्रभावित करने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को

- तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 में हुए दंगों के मामले में कथित तौर पर हाथ होने का आरोप लगाते हुए बदनाम करने की साजिश रची थी।

नियमित जमानत दे दी। सीतलवाड़ पर गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उन दंगों के मामले में कथित तौर पर हाथ होने के लिए बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप हैं। (शेष पृष्ठ 5 पर)